महत्वपूर्ण एवं खास

भालू के हमले से घायल हुआ कृषक

खरसिया (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक के पतरापाली गाँव में सुबह के समय कृषक कार्तिकेश्वर राठिया खेत गए थे उसी दौरान भालू से आमने सामने हो गए और दोनों के बीच भीडंत हो जाने से कार्तिकेश्वर घायल हो गया तुरंत सुचना पाते ही वन विभाग से परिक्षेत्र रक्षक रामप्रसाद डनसेना पहुँच कर तत्काल सिविल अस्पताल खरसिया पहुचाए वहाँ उनका उपचार जारी है।

पानी में डूबने से छात्र की मौत, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

कोरबा (आरएनएस)। जिले में परसाखोला झरना के पिकनिक स्पॉट में हादसा हो गया। जहां नहाने गए छात्र की डूबने से मौत हो गई। छात्र दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यहां आया हुआ था। इसी दौरान नहाते समय छात्र पानी में डूब गया। दोस्तों की चिख-पुकार के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने छात्र को पानी से बाहर निकाला। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया है। बालको पुलिस केस दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है।

पति को सामान लेने भेजने के बाद गुम हुई पत्नी

कोरबा (आरएनएस)। पत्नी के साथ घर से निकला पति उस समय परेशान हो गया जब बस में बैठी पत्नी अचानक अदृश्य हो गई। सरसिवा बलोदा बाजार निवासी पति की रिपोर्ट पर कोरबा पुलिस ने गुम इंसान कायम कर लिया है। सरसीवा बलौदा बाजार निवासी राजू साहू अपनी पत्नी यशोदा साहू के साथ कोरबा पहुंचा बस स्टैंड में चिरमिरी जाने वाली बस पर दोनों सवार हुए। पत्नी ने कहा भूख लगी है कुछ खाने के लिए ले आओ। पति नीचे उतरा खाने का सामान लेकर जब वह वापस लौटा तो पत्नी सीट से गायब थी। आसपास तलाशने के बाद पति यानी राजू साहू सीएसईबी पुलिस चौकी पहुंचा और आप बीती सुनाया। राजू साहू से पूछताछ में पता चला है कि उसकी पत्नी यशोदा ने मोबाइल पर मैसेज भेजा था कि मैं कहीं जा रही हूं वापस घर चले जाना। बहरहाल राजू साहू पुलिस के साथ मिलकर अपनी पत्नी की तलाश में है। देखना है उसे सफलता मिलती है अथवा नहीं।

खेत में मिली युवती की अर्धनग्न लाश, जांच में जुटी पुलिस

जांजगीर (आरएनएस)। जांजगीर जिले में एक 22 साल की युवती की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली है। युवती सोमवार रात को अचानक घर से लापता हुई थी। अगले दिन मंगलवार को उसकी लाश गांव के ही एक खेत में फसल के बीच में पड़ी मिली है। मौके पर उसे घसीटने के निशान भी मिले हैं। इसके चलते पुलिस ने युवती की हत्या की आशंका जताई है। जांजगीर जिले के डभरा थाना क्षेत्र के कुधरी गांव की है। युवती अचानक रात को घर से लापता हो गई थी। परिजनों को पता चलने पर वे उसकी तलाश कर रहे थे। इसके बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह जब गांव में कुछ लोग खेत में काम करने गए तब युवती का शव गांव के सरंपच के खेत के पीछे वाली खेत में पड़ा देख घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी है।शव एक दीवार से लगे खेत में फसल के बीच में पड़ा हुआ था। युवती के सिर और हाथ पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। युतवी का घर से कूछ दूर पर एक खेत के पास चप्पल मिली हैं। उसी स्थान पर उसके प्रेमी गुलेश अंचल का भी एक चप्पल मिला है। मामले को लेकर एसडीओपी भवानी शंकर खूंटिया ने के अनुसार युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही गुलेश अंचल के साथ चल रहा था। घटना के बाद से ही गुलेश लापता है। हम इस मामले में अलग-अलग एंगल से अभी जांच कर रहे हैं। शव को पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट इनवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 जनवरी में

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे औपचारिक घोषणा

» लोगो और वेबसाइट की लांचिंग भी होगी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इंवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन जनवरी 2022 में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 सितंबर को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री इनवेस्टगढ़-छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट भी लांच करेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इंवेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी 2022 से 01 फरवरी 2022 तक रायपुर में किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक-समुदायों, ग्लोबल कंपनियों, बिजनेस लीडरों, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय व्यवसायियों, व्यापरिक एवं निवेशक संगठनों, सप्लायरों, डिस्ट्रीब्यूटरों, बिजनेस इनोवेटरों, विचारकों, उद्यमियों को एक-दूसरे के नजदीक आने का अवसर मिलेगा।

वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नयी सरकार के गठन के बाद नये

औद्योगिक और आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्ववाली सरकार ने नयी उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी हैं। साथ ही उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58 हजार 950 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में इस अवधि में 1564 नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

इस समिट के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश के लाभ, परस्पर सहयोग, पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति की उन संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी, जिसके जरिये राज्य का विकास और तीव्रता से हो पाए। साथ ही समिट के जरिये राज्य के निवासियों के लिए अच्छे वेतनवाली नौकरियां पाने, कार्यकुशलता निखारने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ स्पर्धा करते हुए व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए संभावनाओं की तलाश की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं - मैं छत्तीसगढ़ में आयोजत हो रहे इस इनोवेटिव इनवेस्टमेंट मीट की मेजबानी के लिए बहुत उत्सुक हूं। वे कहते हैं- विश्व की अर्थव्यवस्था अब कोविड के संकट से उबर रही है, ऐसे समय में वैश्विक निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ एक मजबूत विकल्प हो सकता है। छत्तीसगढ़ में निवेश उनकी वैश्विक गतिविधियों के संचालन और आर्थिक क्षतिपूर्ति का जीवंत जरिया बन सकता है। छत्तीसगढ़ में सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां ग्लोबल कंपनियों के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली, अच्छी कनेक्टिविटी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के फायदों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने और निरंतर उन्नति करने रहने के अच्छे अवसर हैं। उन्होंने कहा कि मैं इनोवेटिव समिट के दौरान छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश के नये और उत्साहजनक अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हूं।

इनवेस्टमेंट मीट 2022 चार बड़े क्षेत्रों- एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन और ग्रीन एनर्जी- में विकास के अवसरों को प्रस्तुत करने का मौका होगा। इन सभी सेक्टरों का अलग-अलग पैवेलियन होगा, जिनमें इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेस, यूनिक प्रोसेसेस, सस्टेनेबल रिसोर्सेस, इनोवेटिव वर्किंग मॉडल, वर्क-फोर्स, क्लाइमेटिक एडवांटेज, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सहित बहुत कुछ प्रदर्शित होगा।

5 सितंबर तक प्रदेश के सभी शिक्षकों एवं स्कूल कर्मचारियों का किया जाएगा टीकाकरण

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वैश्विक महामारी की वजह से प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से शासन द्वारा स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिससे कि बच्चों को इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के मद्देनजर स्थिति का आंकलन कर सरकार द्वारा सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को खोले जाने का निर्णय लिया जाना है।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार 5 सितम्बर 2021 तक राज्य के सभी सरकारी एवं निज़ी स्कूलों के शिक्षकों एवं स्कूल शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्य जो 18 वर्ष से अधिक के हों का टीकाकरण, अभियान के रूप में किया जाना है।

अभियान के अंतर्गत जिन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कोविड टीके की प्रथम खुराक दी जा चुकी है, उन्हें समय पर दूसरी खुराक दी जानी है। वहीं जिन शिक्षकों, स्कूल कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को कोविड टीका की एक भी डोज़ नहीं दी गई है उनका जल्द से जल्द कोविन पोर्टल में पंजीकरण कर टीकाकरण किया जाना है।

स्कूलों के साथ-साथ अब आश्रम-छात्रावास भी खुलेंगे

» मुख्यमंत्री तवाडबरा ग्राम के राजमेरगढ़ पारा के पंच रमेश बैगा के घर पहुंचे और उनके साथ किया जलपान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही प्रवास के दौरान एक बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती के आग्रह पर जिले में आश्रम-छात्रावासों प्रारंभ करने की घोषणा की। सरस्वती का गांव उसके छात्रावास से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ग्राम तवाडबरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के निरीक्षण के दौरान बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती बैगा ने मुख्यमंत्री बघेल से कहा कि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आश्रम-छात्रावास नहीं खुलने से वे अपने स्कूल नहीं जा पा रही हैं। सरस्वती ने गौरेला के ज्योतिपुर स्थित छात्रावास प्रारंभ कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। सरस्वती ने बताया कि वे टीकरकला स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। उनके गांव से ज्योतिपुर छात्रावास की दूरी 20 किलोमीटर है। इस वजह से वह स्कूल प्रारंभ होने के बावजूद अपने स्कूल नहीं जा पा रही है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती की समस्या को पूरी

संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हुए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आश्रम-छात्रावास प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से सुदूर अंचलों के गांवों के छात्र-छात्राओं के लिए अपने स्कूलों में पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा। लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर सुदूर अंचलों के गांवों के छात्र अपने नजदीकी आश्रम-छात्रावास में रहकर स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा से बच्चों की इस समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ग्राम पंचायत ठाड़पथरा के तवाडबरा ग्राम के राजमेरगढ़ पारा के पंच रमेश बैगा के घर पहुंचे और उनके साथ जलपान किया। उन्होंने वहां ग्रामीणों से बातचीत की एवं उन्होंने घर के शगुन के तौर पर 2000 रूपये गृह लक्ष्मी को दिए।

ड्रायविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाईन 1-ए प्रमाण-पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य

रायपुर (आरएनएस)। वाहन चालाकों की सुविधा के लिए ड्रायविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके तहत अब तक प्रदेश के 22 हजार 219 लोगों ने ऑनलाईन के माध्यम से इस यूजर फ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्रायविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिक्रेट को ऑनलाईन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था।

कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा हुई है। साथ ही आवेदकों को फर्जी एजेंटों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है।

दरअसल मोटरयान अधिनियम के तहत ड्रायविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण देने का नियम है। जिसके लिए आवेदकों को एजेंटों व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोरोना काल में आवेदकों को मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इससे राहत पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रारंभ की है। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के 22 हजार से अधिक आवेदक उठा चुके हैं और इससे मेडिकल प्रमाण-पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगी है।

इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन मेडिकल सर्टिफिक्रेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आवेदक यदि 40 वर्ष से अधिक उम्र का है और लायसेंस बनवाना चाहता है, तो उसे फार्म-ए में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है, ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए ड्रायविंग लाइसेंस के आवेदक को फार्म भरने के बाद डॉक्टर के पास जाना होगा और अपना आवेदन नम्बर बताना होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सत्तर अधिकारी बनेंगे डीएसपी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज गृह (पुलिस) विभाग में सत्तर निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने हेतु विभागीय चयन समिति की कार्यवाही पूर्ण की गयी जिससे वर्षों से पदोन्नति हेतु आशान्वित निरीक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार विभागों की समीक्षा की जा रही है जिसमें उनके द्वारा वर्षों से लंबित माँगों को पूर्ण किए जाने हेतु त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा विभागीय समीक्षा के दौरान विषम परिस्थितियों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के मनोबल में वृद्धि हेतु तत्काल पदोन्नत्ति की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे जिसके पालन में आज यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल पदोन्नति सूची जारी करने के निर्देश भी आज अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न सिर्फ़ अधिकारियों/ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है अपितु उनमें कार्य हेतु नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है।

वन भूमि पट्टाधारियों को मिलने लगा शासकीय योजनाओं का लाभ

» 4 हजार से अधिक पट्टाधारियों को मिला आशियाना

रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर जिले के वनांचल इलाकों में वनभूमि पर वर्षों से काबिज वनवासियों को भूमि के उपयोग का मालिकाना हक देने के बाद उन्हें शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि उनके जीवनस्तर में बदलाव आ सके और वह भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर तरक्की और खुशहाली हासिल कर सके। बिलासपुर जिले में वनभूमि पट्टाधारियों की संख्या 6 हजार से अधिक है। जिला प्रशासन के पहल से अब तक लगभग साढ़े पांच हजार से अधिक वनपट्टाधारियों को विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से लाभान्वित किया जा चुका है। पट्टे पर दी गई वनभूमि को खेती के लायक बनाने के साथ ही शासन उन्हें सिंचाई, खाद-बीज, पशुपालन, मछलीपलन जैसी आजिविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने में लगा है। वनभूमि पट्टाधारियों को प्राथमिकता से पक्का आवास सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है।

बिलासपुर जिले में वन अधिकार के तहत प्राप्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 हजार 360 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध हो चुका है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले 617 हितग्राहियों के 191.350 हैक्टेयर भूमि में समतलीकरण एवं मेड़ बंधान का कार्य कराया गया है। जिसके लिए शासन द्वारा 2 करोड़ 27 लाख 38 हजार रूपए स्वीकृत किए गए। मनरेगा के कन्वर्जेंस से 80 हितग्राहियों के 40 हैक्टेयर से अधिक भूमि में बकरी पालन एवं कुक्कुट पालन के लिए शेड निर्माण किया गया।

जिले में 472 हितग्राहियों के खेतों में सिंचाई सुविधा के लिए नलकूप, कुंआ, स्टाप डेम तथा आजीविका के लिए नाडेप टांका एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन हेतु 6 करोड़ 20 लाख 40 हजार रूपये स्वीकृत किए गए। सिंचाई हेतु 368 हितग्राहियो के भूमि पर डबरी निर्माण के लिए 4 करोड़ 30 लाख 56 हजार रूपये और 84 लाभार्थियो के भूमि पर कुंआ निर्माण के लिए 1 करोड़ 85 लाख 78 हजार रूपये खर्च किया गया। आजिविका के लिए 11 हितग्राहियों को उनकी भूमि में 1 लाख 54 हजार रूपए की लागत से नाडेप टांका निर्माण किया गया है तथा 9 हितग्राहियों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए 2.5 लाख रूपए स्वीकृत किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा समर्थक हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बॉर्ड के सदस्यों कुश सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आकलन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धांतिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को प्रत्येक कार्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् उक्त पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैद्धांतिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सक्रियता का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पधारिए ... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं हर्बल उत्पाद

» प्रसंस्करण इकाईयों में मिल रहा वनवासियों को रोजगार

रायपुर (आरएनएस)। वनोपज वहां के रहवासियों के लिए जिविकोपार्जन का आधार बन रहा है। जंगलों में पाए जाने वाले बहूमूल्य ईमली, महुआ, चार, हर्रा-बेहड़ा व अन्य वनोपज के संग्रहणकर्ता को तो इसका लाभ मिल ही रहा है वहीं इसके प्रसस्करण से बनने वाले उत्पाद लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इससे बनने वाले हर्बलउत्पाद बीमारियों से बचाव के लिए भी कारगार है। वनों में बिखरे इस खजाने को आमजनमानस को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार इसे उचित मूल्य पर खरीदी कर रही है। धमतरी जिले के नगरी के दुगली में स्थापित वन धन विकास (लघु वनोपज प्रसंस्करण) केन्द्र में एलोवेरा शैम्पू, बॉडीवॉश, जैल, जूस के साथ ही मूसली लड्डू और वज्रदंती हर्बल पावडर का उत्पादन किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रसंस्करण केंद्र पर कार्यरत स्व-सहायता समूह के सदस्यों की तारीफ की थी।

वन विभाग द्वारा प्रसंस्करण केन्द्र में संसाधन के साथ ही समय-समय पर नई तकनीकों का प्रशिक्षण और मशीन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद तैयार उत्पाद को स्थानीय स्तर पर अगर खरीददार तय दर पर लेने पहुंचे तो, उन्हें बेच दिया जाता है। साथ ही एन.एफडब्ल्यू.पी. मार्ट में तैयार उत्पाद बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यहां पर सितंबर से जनवरी तक शतावर का पाउडर तैयार किया जाता है जो कि महिलाओं, खासतौर पर शिशुवती माताओं के लिए पौष्टिकता से भरपूर होता है। आंवला से मीठा व नमकीन कैण्डी, जूस, पाउडर बनाने का काम अक्टूबर से फरवरी में होता है। वहीं तिखुर पाउडर बनाने का काम दिसंबर से फरवरी तक, बैचांदी से चिप्स बनाने का काम दिसंबर से फरवरी तक होता है। जो कि कृमिनाशक होने के साथ ही फ्लाहारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहां कार्यरत महिला समूह को मार्च से जून तक केकती से सूखा रेशा बनाने का काम भी मिलता है। इसके रेशे से रस्सी बनाकर पायदान, थैला इत्यादि बनाया जाता है और वन विभाग के उत्पादन क्षेत्रों में भी इसे बाड़ी के तौर पर लगाया जाता है। हाल ही में यह प्रदेश का ऐसा पहला वन-धन केन्द्र बना, जहां एलोवेरा से जैल, बॉडीवाश, शैम्पू और जूस तैयार किया जा रहा है।

इस प्रसंस्करण केन्द्र में यहां रहने वाले कमार जनजाति के लोग शहद लाकर बेचते हैं। पहले यह शहद स्थानीय व्यापारियों को सस्ते दर में बेच दिया करते थे, किन्तु इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने पर कमार जनजाति के लोग प्रसस्करण केंद्र में बेचकर उचित दाम पा रहे हैं।